

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 118/2021

मोहन सिंह पुत्र सवाईसिंह, जाति राजपूत, निवासी ककराना, उप तहसील गुढा गौड़जी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

-अपीलार्थी-

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये नायब गुढा गौड़जी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

-रेस्पोंडेंट-

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी
उनवानी सरकार बनाम मोहन सिंह अंधारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 03/2021 निर्णय दिनांक 14.06.2021

उपरिस्थिति:-

1. श्री धीरज कुमार बोयल, एडवोकेट -----अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक -----रेस्पोंडेन्ट की ओर से ।

-निर्णय-

दिनांक 30.09.2022

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 14.06.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मोहन सिंह मु0नं0 03/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि - अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी ने हल्का पटवारी ककराना द्वारा भूमि खसरा नंबर 631 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म गैर.मु. नाला के 0.11 हैक्टर व खसरा नंबर 1233/632 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. नाला के 0.09 हैक्टर रकबे पर मोहनसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी ककराना ने मकान व चारदिवारी लगाकर अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को धारा 91 एल.आर. एक्ट के अंतर्गत नोटिस भेजा गया। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट की पत्नी घर पर मिली और नोटिस लेने से इन्कार किया जिसको तामिल मानते हुये अपीलांट के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जबकि अपीलांट परिवार सति उड़िसा रहता है। प्रार्थी के घर पर कोड



जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

प्रार्थी की तामिल गलत मानी गई है। ना प्रार्थी की तामिल हुई और ना ही अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को जवाब देही को कोई अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा अपीलांट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। विवादग्रस्त भूमि पर बने मकान पुश्तैनी है अपीलार्थी का कोई नया अतिक्रमण नहीं है। हल्का पटवारी ने अपीलार्थी के खिलाफ झूठी शिकायत की है। अपीलार्थी की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गई, आदि।

अंत में अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2021 को निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि— अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा विवादित भूमि का मौका निरीक्षण नहीं किया गया, केवल हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलांट के विरुद्ध बिना तामिल करवाये एक पक्षीय बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट परिवार सहित उड़िसा रहते हैं। उनके घर पर कोई नहीं रहता। तामिल के संबंध में गलत रिपोर्ट की गई है। विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का पुराना कब्जा है, नया अतिक्रमण नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी का निर्णय दिनांक 14.06.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय दिनांक 14.06.2021 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

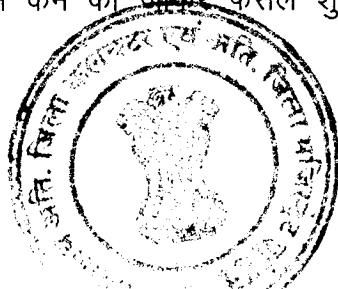
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट परिवार सहित

जानि. किरा. कलेक्टर
द्वारा

उड़िसा रहता है और उनके घर पर कोई नहीं रहता। तामिल कुन्निदा द्वारा अपीलांट की पत्नी घर पर मिली और नोटिस लेने से इन्कार किया गया, गलत रिपोर्ट की गई है और न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा तामिल पर्याप्त मानकर अपीलांट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये बेदखली का आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही बेदखली का आदेश पारित किया गया है। विवादित भूमि पर उनका काफी वर्षों पूर्व, पूर्वजों के समय से ही पुराना कब्जा है आदि।

मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये बेदखली का आदेश पारित किया गया है और अपीलांट का यह कथन कि वह परिवार सहित उड़िसा रहते हैं, उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2021 उनवानी सरकार बनाम मोहन सिंह मु0नं0 03/2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण करेंगे तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधि सम्मत कार्यवाही करेंगे। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जगदीश प्रसाद गौड़
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
उड़िसा

जगदीश प्रसाद गौड़
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
उड़िसा